तेलंगाना के इतिहास का संक्षिप्त विवरण

तेलंगाना सदियों से पिछड़ा हुआ रहा है। यह कभी ब्रिटिश नियंत्रण में नहीं रहा तथा यहां हैदराबाद के निज़ाम का शासन रहा था। उन्होंने फ्रांस के साथ मिलकर वारंगल में कुछ कारखानों और एक टेक्सटाइल मिल की ज़रूर स्थापना की थी। लेकिन रोजग़ार के अवसर बहुत कम थे तथा क्षेत्र में सामंतवादी चलन के कारण शोषण बढ़ता गया।

कृष्णा और गोदावरी दोनों नदियां होने के बावजूद तेलंगाना में सिंचाई प्रणाली जैसी सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधा को कभी व्यवस्थित ढंग से विकसित नहीं किया गया। असमानता के कारण तटीय आंध्र क्षेत्र ने आक्रामकता के साथ इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और नहरों के ज़रिए इन नदियों का पानी पूर्व और पश्चिम गोदावरी जिलों में लाया गया। तेलंगाना क्षेत्र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ बन गया और पहली बार यहीं से भारत में सशस्त्र संघर्ष सामने आया।

1956 में फज़ल अली ने जब राज्यों के भाषा के आधार पर पुन:गठन पर अपनी रिपोर्ट पेश की थी तब तेलंगाना (हैदराबाद राज्य) ने पहले तो विलय करने से इंकार कर दिया लेकिन उसके बाद इस पर काफी लंबी चर्चा की गई कि किन शर्तों पर वह आंध्र प्रदेश का हिस्सा बनेगा। नेहरू द्वारा 'सज्जनों का समझौता' कहे जाने वाले इस समझौते का प्रारूप तैयार किया गया जिसमें तेलंगाना को 'लगभग ' एक अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई।

ऐसा नहीं हो सका और अलग राज्य के लिए आंदोलन जारी रहा। 1960 और 1970 के अंत में डॉ. एम. चन्ना रेड्डी ने अलग तेलंगाना के आंदोलन को व्यंग्यपूर्वक हवा दी जो खूनी दंगों का कारण बना लेकिन आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का स्थायी प्राधन्य सुनिश्चित कर दिया। जब श्री एन टी रामा राव ने तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) की स्थापना की तब तटीय आंध्र में कांग्रेस का प्रभाव कम हो गया लेकिन तेलंगाना और रायलसीमा में उसका प्रभुत्व बना रहा।

श्री के चंद्रशेखर राव ने 2001 में तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) का गठन किया। राव ने विधानसभा के उपाध्यक्ष पद और टीडीपी से इस्तीफा दे दिया। 2001 में आंध्रप्रदेश के स्थानीय निकाय के चुनावों में टीआरएस मज़बूती के साथ सामने आई। इसमें टीडपी को 20 में से केवल 10 जिला परिषदों में जीत हासिल हुई। ऐसे में कांग्रेस ने झट से लोकसभा चुनावों के लिए टीआरएस के साथ समझौता कर लिया। 2004 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जो टीआरएस ने कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े थे उसमें पार्टी को विधानसभा की 26 और लोकसभा की पांच सीटें मिली। जब टीआरएस को लगा कि कांग्रेस तेलंगाना मुद्दे पर टाल-मटोल कर रही है तब उसने यह गठबंधन तोड़ दिया।

(यह जानकारी बिज़नज़ स्टैण्डर्ड में अदिति फडनिज़ के लेख से ली गई है।